

are no more Members of this House or the other House.....

**SHRI SAMAR GUHA :** Most of the Members, 95 per cent of them are no more members of this House or the other House.

**SHRI R. K. KHADILKAR :** That is a suggestion. Regarding the other thing, this is too general a statement. I do not think this is the state of affairs.

### कृषि विकास के लिए बिहार को केन्द्रीय सहायता

994. श्री रामावतार शास्त्री : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कृषि विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :**  
(क) जी, हां ।

(ख) और (ग). बेमौसमी और अधिक वर्षा के कारण रबी की फसलों की महान क्षति के कारण बिहार सरकार ने रबी बीज की अधिक प्राप्ति और प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों को ऋण सुविधायें प्रदान करने के लिए एक करोड़ रुपये का लघु कालीन ऋण मांगा है। यह मंजूर कर दिया गया है ।

**श्री रामावतार शास्त्री :** इसी सदन में 1 जुलाई को बिहार में असामयिक वर्षा के कारण हुई क्षति के सवाल पर बहस हुई थी। इस विषय पर बिहार सरकार को केन्द्रीय सरकार के बीच विवाद शुरू हो गया है। केन्द्रीय सरकार के अनुसार बर्हा पर 20 से 25 फीसदी तक क्षति हुई है, जबकि बिहार के राजस्व मंत्री कहते हैं कि 80 से 90 फीसदी तक क्षति हुई है। मैं यह

जानना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कृषि के विकास के लिए जो सहायता मांगी है, उसके सम्बन्ध में उसने क्षति का क्या व्यौरा दिया है, जिसके आधार पर केन्द्रीय सरकार ने 1 करोड़ रुपये देने की बात कही है ।

**श्री शेर सिंह :** मेरे पास तो कोई इनफॉर्मेशन नहीं है। बिहार सरकार की ओर से इस प्रकार की कोई डेफिनेट इनफॉर्मेशन नहीं आई है ।

**श्री रामावतार शास्त्री :** बिहार सरकार का कहना है कि वहां पर बहुत अधिक क्षति हुई है। उन्होंने कोई न कोई व्यौरा जरूर भेजा होगा। बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच यह बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। अगर बिहार सरकार ने कोई व्यौरा नहीं दिया है, तो केन्द्रीय सरकार ने पैसा किस आधार पर दिया है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या बिहार सरकार ने कर्जों और बीज के अलावा भी कोई मांग की है। मसलन कृषि के विकास में ट्यूबवैलज का बड़ा महत्व है। क्या हम बारे में बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई निवेदन किया है ; अगर हां, तो उसके बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**श्री शेर सिंह :** उन्होंने ट्यूबवैलज के लिए कोई विशेष मांग नहीं की है। लेकिन पिछले साल बिहार के कृषि मंत्री ने एक पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने बिहार की एग्रीकल्चर की समस्याओं के बारे में उल्लेख किया था। उस पत्र में पांच छः बातें थीं ।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, मिनिस्टर साहब सिर्फ उसका जवाब दें। अगर वह अपने जवाब में और बातें कहेंगे, तो उन्हें उनके बारे में भी जवाब देना पड़ेगा ।

**श्री शेर सिंह :** मैंने बता दिया है कि बिहार सरकार ने ट्यूबवैलज के बारे में अलग से कोई मांग नहीं की है। उसने कुछ और बातों के बारे में मांग की है ।

श्री रामाबतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि इस बारे में बिहार सरकार ने क्या ब्यौरा दिया है, क्योंकि अगर उसने कोई ब्यौरा नहीं दिया है, तो केन्द्रीय सरकार ने पैसा किस आधार पर दिया है।

अध्यक्ष महोदय बिहार सरकार ने जो और बातें कही हैं, वे भी बता दीजिये।

श्री शेर सिंह : पिछले साल बिहार सरकार ने इन स्वोमो के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की है : रूरल कम्प्यूनिकेशन एण्ड मार्केटिंग काम्प्लेक्स, सायल कान्जरवेशन, फिश-रीज। उसका कहना है कि बिहार में स्माल फार्मर्ज डेवलपमेंट गेजेन्सी के लिए एक और पायलट प्राजेक्ट दिया जाये। उसने मार्जिनल फार्मर्ज और एग्रीकल्चरल लेबरर्ज के लिए एक स्कीम भेजी है। उसने बिहार में सेंट्रल मीड फार्मर्ज बनाने के लिए कहा है और एक प्लाट प्रोटेक्शन की स्कीम भी भेजी है। उसकी मोटी मोटी मांगें ये थी।

श्री ए० पी० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो केन्द्र की तरफ से बिहार को सहायता दी गयी वह सूखे की क्षति पूर्ति करने के लिए दी गई या कृषि के विकास के लिए? किस बात के लिए सहायता दी गई?..... (व्यवधान) ..... एक करोड़ रुपया जो दिया वह ड्राउट के लिए है या.....

श्री शेर सिंह : नहीं, ड्राउट के लिए नहीं है। यह तो रबी के बीज के लिए है।

श्री ए० पी० शर्मा : जो ड्राउट हुआ उसकी क्षति की पूर्ति के लिए आपने कोई बसिस्टेंस दिया ?

अध्यक्ष महोदय : यह क्षति का सवाल नहीं है।

श्री शंकर बयाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि बिहार

सरकार ने आपको यह लिखा है कि जो यह स्टडी टीम गई थी वहां देखने के लिए उसकी रिपोर्ट सही नहीं है इसलिए दूसरी स्टडी टीम भेजी जाये जो कि क्षति का मूल्यांकन करके आये कि कितनी क्षति हुई है और कितने की सहायता आप दे सकते हैं, तो क्या आप दूसरी स्टडी टीम भेज रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह स्टडी टीम का सवाल नहीं है। इसमें तो जो उन्होंने मांगा डेवलपमेंट के लिए, यह एक डेफिनिट रकम है।

श्री रामदेव सिंह : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या बिहार सरकार ने एग्रीकल्चर लोन जो कोआपरेटिव सोमायटीज के माध्यम से दिया जाता है, उसकी बसूली नहीं हो रही है और सभी गमिनियां तथा कोआपरेटिव बैंक इस पोजीशन में नहीं हैं कि वह रिजर्व बैंक में पैसा ले सके, इसलिए बिहार सरकार ने क्या शेरर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगा है?..... (व्यवधान)..... इसमें इसी प्रकार की बात आई है, यह एग्रीकल्चर कोआपरेटिव लोन जो है यह एग्रीकल्चर के ही विकास से संबंध रखता है..... जो मूल प्रश्न है उसी से यह संबंधित है। 20-22 करोड़ रुपया जो बिहार में कोआपरेटिव के माध्यम से उपलब्ध किया जाता था लोन की बसूली नहीं होने से किमानों के लिए वह उपलब्ध करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ क्या शेरर कैपिटल में सरकार कंट्रीब्यूट करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इसमें से नहीं निकलता।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि इस क्षति का ब्यौरा बिहार सरकार से नहीं प्राप्त हो पाया है तो क्या क्षति का ब्यौरा जानने के लिए सरकार कोई कदम उठायेगी ?

श्री शेर सिंह : उसके लिये स्टडी टीम भेज कर पता लगायेंगे कि कितनी क्षति हुई है। लेकिन

क्षति हुई है। इसीलिए यह रुपया एक करोड़ दिया है।

श्री ए० पी० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने पूछा कि यह क्षति की वजह से दिया गया तो उस वक्त आप ने भी कहा कि यह क्षति के लिए नहीं बल्कि कृषि के विकास के लिए है। अभी उन्होंने कहा कि क्षति हुई है यह रुपया इसी लिए दिया गया है।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : मंत्री महोदय यह दताने की कृपा करेंगे वाटर लाइगिंग से जो नुकसान हुआ उसके लिए भी कुछ रुपया रखा है।

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस योजना में जो हर साल की योजना बनती है उसमें ब्लाक ग्रान्ट और ब्लाक लोन दिया जाना है। अब उसमें यह स्टेट सरकार की इच्छा की बात है, वह किस काम में उसको इन्वेस्ट करना चाहती है।

#### Industrial Relations in Durgapur Steel Plant

\*996 SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Industrial relations in Durgapur Steel Plant have improved ;

(b) if so, whether some sort of Joint Consultation Machinery have been formed ; and

(c) if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Except the Works Committee constituted according to the provisions of the Industrial Disputes Act, no other Joint Consultative Committee is functioning due to non-participation by the recognised Union.

SHRI S. M. BANERJEE : It is very disheartening to note that industrial relation in

Durgapur steel plant has not improved. I would like to know whether it is a fact that after the recent agreement with various trade unions in Durgapur Steel Plant, there were certain demands made by the employers representative about the joint consultative machinery for lasting industrial peace and since the existing machinery has been found to be ineffective, I would like to know whether they would evolve some joint consultative machinery on this.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN : The management is very keen to associate the workers and we have been trying to form various committees, but the difficulty is that the biggest union which is the recognised union has not responded to our efforts so far. But the efforts are still continuing.

SHRI S. M. BANERJEE. I am happy, the management has decided to associate workers in the various committees including 2 men on the Board of Directors. But, what will be the method ? How do you select or elect those candidates ? I want to know whether in the absence of unanimity among trade unions they will resort to secret ballot so that true representative comes as representative of the workers.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN : I think at this stage it is too early to give any definite procedure for selection of workers representative. As he knows there is a Joint Negotiating Committee which negotiated for wages of workers and they have done extremely good work. We have requested that committee to continue its good work and suggest the best method of selecting representative.

श्री राम सहाय पांडे : श्रीमन्, दुर्गापुर स्टील प्लान्ट हमारे देश का वह प्लान्ट है जिस में 500 करोड़ रुपया हम ने देश का इन्वेस्ट किया है और बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्लान्ट है। पांडेय रिपोर्ट के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि 37 परसेंट जो आप का आज उत्पादन हो रहा है, उस को बढ़ाने के लिए टेकनिकली आप क्या कर रहे हैं ताकि उस का प्रोडक्शन बढ़े और जो स्टाफ कैंपेसिटी है वह बढ़े।